The question was put and the motion was adopted.

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपना विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1979

(*Insertion of New Article* 165-A)

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभापति महोदय, बादव में इस सदन से दरख्वास्त करता हूं कि वह मुझे भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान करें ।

The question was put and the motion was adopted.

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपना विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

THE ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 1977

(*Amendment*) *of Sections* 2 *and* 5)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Hamida Habibullah.

SHRI SHYAM LAL YADAV (Uttar Pradesh): Before we proceed, Sir, I have to make a request. I would like to say that this Bill, as is evident, was introduced in the year 1977 and this has been discussed in this House during the past few years. During the past four sessions, we have discussed it and this is the fifth session that we are discussing this Bill. If the House proceeds in this manner in considering one simple Bill, it means the Bills of the other Members which are pending in the House, will never be taken up during our tenure of mmebership of this House. Therefore, my respectful submission to you is that you kindly fix some time limit today for the consideration and passing of this Bill and then the next Bill may be taken up.

Secondly, Sir, I would request that for future non-official Bills also you may kindly allot the time every week for the Bills and for the Resolutions also and I think the whole House will agree to this proposal because Members' Bills and Resolutions are pending. If one Resolution or one Bill is taken up for the whole period of membership of a Member then we will have no other Bills or Resolutions. Therefore, my submission is that today at least, you may kindly fix some time limit by which this Bill can be considered.

Sir, a definite time is allotted to Government business. The number of hours for a particular business is fixed and I do not see why we cannot fix up a time limit for the non-official business also...

SHRI TRILOKI SINGH (Uttar Pradesh): This Bill has been discussed already during six sittings.

SHRI SHYAM LAL YADAV: That is why I say it. For the official business, 3 hours or 5 hours or 6 hours are allotted; one day may be allotted to some business but there is some time limit. In the same manner, we can also allot a definite time limit for the non-official Bills and Resolutions. Therefore, Sir, I think the whole House will agree with me. You may kindly fix some time limit for consideration and passing of this Bill today before 5 P.M. so that other Bills which are pending may be taken up. That is my submission.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभापति महोदय, मुझे भी यह बात उठानी है कि यह विधेयक जो त्रिलोकी सिंह जी का है इसको खत्म करने के लिये कुछ समय निर्धारित करें । कितने समय से यह चला आ रहा है और

इसी की वजह से बहुत से निजी विधेयक ब्लाक्ड हैं। इसलिये मेरा कहना है कि कोई समय निर्धारित किया जाए जिस तरह से आप रेजोलूशन के लिये और दूसरे काम के लिये समय निर्धारित करते हैं। इस विधेयक का भी अंत होना चाहिये, नहीं तो यह लम्बा चला जा रहा है और हम सब के विधेयक ब्लाक्ड पड़े हैं। आप कोई समय निर्धारित करके इसको खत्म कीजिए।

दूसरी बात जो उन्होंने उठाई है ठीक उठाई है। जो संशोधन इन्होंने दिया है इस संशोधन से विधेयक का रूप दूसरा हो जाता है। जिस विधेयक का जोरदार शब्दों में विरोध किया गया था थोड़ी देर के लिये अब उस पर दूसरी तरह से सोचना पड़ता है। इन्होंने इससे अपने विचार को बदला है और ठीक ढंग से बदला है इसलिये संशोधन लाये हैं। अब यदि इस पर बहस कराना चाहते हैं तो जो बिल गये हैं फिर से सब को मौका दिया जाए। साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक समय निर्धारित करके इनको खत्म करने का फैसला किया जाए।

श्री प्रकाश महरोत्रा (उत्तर प्रदेश) : माननीय, जब मिनिस्टर का रिप्लाई हो चुका है तो अब तो वोटिंग होना ही रह गया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The problem raised by the hon. Members is really a genuine one. The practice in our House is that we do not fix time so far as non-official business is concerned, whether they are Bills or Resolutions. But this idea of having some limit for Resolutions and other private Members' Bills has been discussed in the Business Advisory Committee; today also it was discussed and I think leaders of the various parties are seized of the problem and I am sure from next meeting onwards—I cannot say exactly, but whenever the next Business Advisory Committee meets—this point will be taken into account.

As regards the present Bill, well, I have with me a list of—in addition to Shrimati Hamida Habibullah—four other names. I am sure we would be able to finish at least these four speeches and then the next procedural step will be taken so far as the next Bills are concerned.

श्रीमती हामिदा हबीबुल्लह (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, यह जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल है इसका मैं स्वागत करती हूं। जैसा कि बताया गया है इस बिल पर पांच दिन तक बहस हो चुकी है। 18 सदस्य इस बहस में हिस्सा ले चुके हैं। मैं मिनिस्टर साहब को याद दिलाना चाहती हूं कि यह बहुत छोटा सा एमेन्डमेन्ट बिल है जो कि यूनिवर्सिटी के माइनोरिटी केरेक्टर से ताल्लुक रखता है। इस यूनिवर्सिटी के साथ बहुत से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। बहुत जमाने से इस पर बहस की जाती रही है। मैं मिनिस्टर साहब से सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि इस बारे में जो हम लोगों को परेशानी है उसको वे दूर करने की कृपा करें। हमें तो यही देखा है कि वे अब इस बारे में क्या करते हैं। आप जानते हैं कि कांस्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 में माइनोरिटी को पूरा अधिकार है कि वे अपने एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स कायम करें। हमारे मुल्क में कई सौ माइनोरिटीज के इंस्टिट्यूशन्स हैं। क्रिश्चियन्स के बारे में एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स हैं। गवर्नमेन्ट उन में कभी कोई दखल नहीं देती है। ऐसी हालत में यह बात समझ में नहीं आती है कि सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही दखल क्यों दिया जा रहा है। इस बारे में काफी बातें हो चुकी हैं और बार-बार सुझाव

[श्रीमति हामिदा हबीबुल्लाह]

कोर्ट के जजमेन्ट का हवाला दिया जाता है। मुसलमानों को इस मुल्क में अपने इंस्टिट्यूशन्स कायम करने का पूरा हक है। इस युनिवर्सिटी पर मुसलमानों की 30 लाख की आबादी और 9 लाख से भी ज्यादा के फंड लगे हुए हैं। मैं तो मिनिस्टर साहब से सिर्फ यह दर्खास्त करना चाहती हूं कि हमारे मुल्क में तरह-तरह के लोग रहते हैं और तरह-तरह के मजहब को मानने वाले लोग इस मुल्क में बसते हैं। इस चमन में, हर फूल और पत्ते को अपनी शान से आगे बढ़ने दीजिये। यह हमारा मुल्क ऐसा है जिसके बारे में कहा गया है कि—

"सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा,
हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा।"

मैं इतना ही कह कर आपका शुक्रिया अदा करती हूं।

श्री बी॰ सत्यनारायण रेड्डी (आंध्र प्रदेश) : उपसभापति जी, यह जो अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी बिल सदन में आया है, इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी हमारे मुल्क में एक अहम युनिवर्सिटी है। जिस तरह से हमारे हिन्दुस्तान में दूसरी युनिवर्सिटीज हैं उसी तरह से यह भी एक युनिवर्सिटी है। हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें सभी मजहबों के लोग रहते हैं और उन सब की यहां पर इंस्टिट्यूशन्स हैं। मैं इस संशोधन के बारे में सिर्फ यह दरखास्त करना चाहता हूं कि इस संशोधन को हमें किसी नुक्तानिगाह की नजर से नहीं देखना है बल्कि प्रेक्टिकल दिक्कतों को भी सामने रखना चाहिए। अगर इस संशोधन से किसी को कोई फायदा होता हो तो उसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। लेकिन इसके साथ-साथ हमें इस चीज को भी देखना चाहिए कि हिंदुस्तान के अन्दर न सिर्फ एक अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी है बल्कि कई और युनिवर्सिटीज भी हैं। इन युनिवर्सिटीज में केवल एक ही मजहब के लोग तालीम नहीं पाते हैं बल्कि सभी मजहबों के लोग तालीम पाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के साथ 'मुस्लिम' लफ्ज अगर आप रखते हैं तो वहां पर केवल मुसलमान ही तालीम नहीं पा सकते हैं बल्कि दूसरे मजहबों के लोग भी तालीम पा सकते हैं। किसी लफ्ज को किसी इंस्टिट्यूशन के साथ जोड़ देने का मतलब यह नहीं होता है कि उसमें सिर्फ उसी मजहब के लोग तालीम पा सकते हैं। हमारे हिन्दुस्तान के कांस्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी आदमी को चाहे वे किसी भी मजहब का हो उसको किसी भी युनिवर्सिटी में तालीम पाने का हक है। तालीम ग्रहण करने में किसी के साथ कोई फर्क नहीं किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश में उस्मानिया युनिवर्सिटी है, आंध्र युनिवर्सिटी है और तिरुपति युनिवर्सिटी है। इनमें सभी मजहबों के लोग तालीम पा सकते हैं। उनमें किसी किस्म का फर्क नहीं किया जाता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसी भी युनिवर्सिटी में सारे हिन्दुस्तान के लोग तालीम पा सकते हैं और खास कर किसी इलाके के लोग किसी युनिवर्सिटी या कालेज वगैरह में वहां की तहजीब व तमद्दुन से, उसके रस्मो-रिवाज से हम किसी किस्म की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो इसमें किसी को मनाही नहीं होनी चाहिए चाहे वह किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो या किसी भी तबके

से ताल्लुक रखते हों यह उनकी अपनी मर्जी की बात है इसके ऊपर किसी को कोई उज्र नहीं होना चाहिए । हिन्दुस्तान में हम सभी यहां सदियों से मिलजुल कर हैं । यहां की तहजीब व तमद्दन सारे जहां में मशहूर है । हम चाहते हैं कि यहां सभी तबके, हिन्दू, मुसलमान पारसी और क्रिश्चियन या किसी भी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग मिलजुल कर रहें और हम सब को मिलकर एक नई तहजीब व तमद्दन को बनाना है जिससे कि यहां के सभी लोग फले और फूलें । हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है जहां सभी का फलने फूलने का मौका है । मैं इसके साथ ही एक चीज और साफ कर देना चाहता हूं कि कभी भी हिन्दुस्तान के लोगों की यह कोशिश नहीं रही कि किसी तबके को खत्म किया जाये या किसी तबके के हकूकों को बढ़ाया जाये और किसी तबके के हकूकों को दबाया जाये । इसकी कभी कोशिश नहीं की गई और यह किसी की मर्जी या इन्टेशन नहीं रही । हिन्दुस्तान उस वक्त ताकतवर और खुशहाल रह सकता है जब कि इसके अन्दर रहने वाले सभी लोग अपना तंग नजरिया छोड़कर आगे बढ़ें । अगर कोई ऐसा सोचे कि हम अपने ढंग से अलग एक इसका ढांचा बनायेंगे तो यह ठीक नहीं होगा । हर एक ऐसा ही सोचेगा तो यह मुल्क के लिये ठीक नहीं होगा । हिन्दुस्तान का क्षीय समुद्र जैसा है जिसमें सभी को फलने-फूलने और आगे बढ़ने का मौका है । तंग नजरिये का यहां पर कोई स्थान नहीं है । किसी को तंग नजरिये से सोचना और काम नहीं करना चाहिए । यहां की जो यूनिवर्सिटीज हैं, कालेज, मदरसा या गांव का कोई छोटा सा स्कूल उसमें सभी को खुलेदिली से, ऊंचे विचारों से और बड़े हृदय से आगे बढ़ना चाहिए । यहां सारे मुल्क की सभ्यता है किसी एक खास तबके की सभ्यता है ऐसा न समझा जाये । यूनिवर्सिटियों को हम एक ऐसा मुकाम समझें जहां सभी लोग बैठें अच्छी तालीम हासिल करने के नुक्तएनजर से जायें न कि अपना किसी खास चीज को हासिल करने के लिये या किसी को उठाने के लिये या किसी को आगे बढ़ाने के लिये जायें । इस चीज के लिये किसी को भी यूनिवर्सिटीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए । इन हालात के साथ मैं यह चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट श्री त्रिलोकी सिंह जी ने पेश किया है वह वाजिब है और उस पर मेरे ख्याल में किसी का कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए ।

SHRI TRILOKI SINGH: Sir, I beg to move that the question be put. The reasons given by me are quite obvious. We are discussing this one line Bill and in this 17 members from all sections of the House have already participated. Therefore, I would most humbly request you to let me move that the question be now put.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But as I suggested in the beginning of the Bill, there are four names here. Two or three have already spoken. There are one or two more speakers. Mr. Krishnan also wants to speak. They are not taking much time and it won't take more than a few minutes.

Yes, Mr. Krishnan.

***SHRI E. R. KRISHNAN (Tamil Nadu):** Mr. Deputy Chairman, I welcome the Bill whole-heartedly for amending the Aligarh Muslim University Act, 1920.

---

*English translation of the Original Speech in Tamil.

[Shri E. R. Krishnan]

Banaras Hindu University has the facilities to teach the Hindu-culture and Hindu civilization. This Bill also provides ways and means to promote the culture and study of Islam.

I would like to stress on the point that it is the bounden duty of the Government to protect the interests of minorities such as Muslims, Christians, Parsees and Sikhs, etc.

Some may question as to why special concession should be given to the Muslims who are also alike other Indian—and thus promote communalism? I may refer to the statement of Rajaji, a great patriot and ex-Governor General of India, given in 1942. He said that we paved the way overselves for the creation of Pakistan by not protecting the interests of Muslims. He told this to Mahatma Gandhi, who was against the partition of the country. Even now it is my view that we could have avoided the partition of the country, had we considered Muslims to be our brothers.

In case we feel that Muslims are realy our brothers, then we should pass the Bill introduced by the hon'ble Member Shri Triloki Singh with a majority of votes.

I may also request the Government Sir, on this occasion that the present Home Minister Shri H. M. Patel should take up necessary steps to declare the birth-day of prophet Mohammad as a national holiday just as on Mahatma Gandhi's Birth-day. Maha Shivaratri, Vinayaka Chaturthi, Sri Rama Navami and Christmas.

So far as our Tamil Nadu Government is concerned, it practices, whatever it preaches, and hence it takes all the measures to protect the interests of Muslims in Tamil Nadu; there are therefore no communal quarrels as they are witnessed in North India.

If we really feel that Muslims are our brothers, then we should act accordingly. Since we do not act so, I feel not only sorry but also very much ashamed of the fact.

Even after the creation of Pakistan, we cannot deny that many Muslims contributed to the growth of democracy and national integration in our country. But, there are some so-called leaders in North-India who always look at Muslims with suspicion and thus cause communal quarrels on the holy occasions such as Sri Rama Navami, Holi and Bakrid etc.

Whatever be the Government at Delhi, led by Congress or Janata, we have been witnessing the communal quarrels in North India every year since independence. There should be a full stop to these quarrels. Therefore, Sir, I would like to reiterate that we should pass this Bill which protects the Islamic culture. This Aligarh University has been established in the interests of Muslims. So far we did not specify that point, it is their right. I welcome this Bill on behalf of my Party and propose that it should be passed.

श्री हरी शंकर भाभड़ा (राजस्थान): उपसभापति महोदय, श्री त्रिलोकी सिंह जी का जो यह बिल है उसके संबंध में पहले तो मुझे यह निवेदन करना है कि अलीगढ़ मुस्लिम युनीवर्सिटी एक्ट में मुस्लिम शब्द मौजूद है उसके बावजूद इसका और अधिक स्पष्टीकरण करने की उनको क्यों आवश्यकता महसूस हुई। मान्यवर, जहां तक अलीगढ़ मुस्लिम युनीवर्सिटी के ऐतिहासिक स्थान पर होने का सवाल है उसको कोई बदल नहीं सकता। उस यूनीवर्सिटी की जो गरिमा है उसको किसी भी शब्दावली से इस एक्ट में जोड़ने-तोड़ने से समाप्त नही किया जा सकता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जैसे विद्वान पैदा किये हैं उन्होंने जो स्थान इस देश में बनाया है उसको भी भुलाया नहीं जा सकता है। इतिहास में इस

यूनिवर्सिटी का अपना नाम है और यह जो एक्ट है यह कोई इतिहास नहीं है। इसका इतिहास अपना अलग है और मैं समझता हूं कि किसी भी युग में कभी भी यह बात नहीं भुलायी जायेगी कि इस यूनिवर्सिटी के निर्माण करने वाले कौन थे और किस प्रकार से उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को खड़ा किया और कितना लाभ इससे इस देश को हुआ। जहां तक कि इस भावना का प्रश्न है केवल इसी भावना को और अधिक मूर्त रूप देने के लिए और अधिक स्पष्ट करने के लिए यह संशोधन लाया गया है। मैं समझता हूं कि भावना का जहां तक प्रश्न है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। आप किसी सत्य को एक बार कहें चाहे सौ बार कहें, एक शब्द में कहें या हजार शब्दों में कहें, सत्य जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा। तो इस यूनिवर्सिटी का श्रीगणेश मुसलमानों ने किया। मुसलमानों की कुछ संस्थाओं ने किया, यह एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है जिसको कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन कानून की अपनी एक अलग भाषा होती है, कानून में प्रयुक्त किये जाने वाले शब्दों का अपना एक उपयोग होता है। कानून के माध्यम से उसमें उपयोग की जाने वाली शब्दावली से अधिकार बनता है और नकारा जाता है। जहां तक यूनिवर्सिटी की परिभाषा इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में दी है :

"University means Aligarh Muslim University."

यह बहुत स्पष्ट है। मैं समझता हूं कि इसको और ज्यादा स्पष्ट करने के पीछे कानून की मंशा कुछ नहीं हो सकती है क्योंकि जब हम किसी बिल पर विचार करते हैं तो केवल भावनाओं पर विचार नहीं करते हैं बल्कि जो उससे उत्पन्न होने वाले कानूनी पहलू होते हैं जो विशेष अधिकार हैं या अधिकारों पर आने वाली जो पाबन्दियां हैं इन सबो पर हमें विचार करना होता है। अतः जहां तक कानून का विषय है यूनिवर्सिटी की जो डेफिनीशन दी गयी है उससे यही बात स्पष्ट होती है कि जिसको इस संशोधन के माध्यम से केवल और अधिक स्पष्ट किया गया है। कानून में कभी कभी कुछ शब्दों को रिडन्डेंट माना जाता है कि वे अनावश्यक हैं। कम से कम शब्द कानून में प्रयुक्त किये जायें और उनका अधिक से अधिक उपयोग हो यही कानून की मंशा होती है। जितने लम्बे चौड़े शब्दों का प्रयोग कानून मे होगा उतना ही अधिक काम्प्लीकेशन होगा। उसमे उतना ही अधिक झगडा फसाद होने की सम्भावना होती है और जहां तक मैं समझता हूं कि इस देश में इस बात को अब बार बार कहने की कोई आवश्यकता नही है कि इस देश की संस्कृति में जो मुसलमानों का योगदान है उसको कभी नकारा जा सकता है। मैं समझता हूं कि कोई भी समझदार व्यक्ति जिसका दिमाग सेन है, शुद्ध है इस बात को नकार नहीं सकता है। जो हो चुका है उसको आज हम अनडू नहीं कर सकते हैं। हमारी संस्कृति में जो धारायें मिली हैं, भिन्न भिन्न धारायें मिली हैं उनको आज अलग नहीं किया जा सकता है। इन धाराओं को एक साथ लेकर ही चलना पड़ेगा लेकिन उस धारा मे मुसलमान की धारा अपने आप अलग होने का प्रयास भले ही कोई करे लेकिन उसको सफलता नहीं मिलेगी। जब सम्मिलन हो जाता है, गंगा और यमुना के संगम के बाद कौन सा पानी गंगा का है और कौन सा यमुना का, यह पता लगाना कठिन है। कोई वैज्ञानिक परीक्षण करने का विश्लेषण करे तो बात दूसरी है। अन्यथा

[श्री हरी शंकर माभड़ा]

इसकी जानकारी प्राप्त करना मनुष्य के लिए कठिन है। भारतीय संस्कृति अनेक संस्कृतियों का सम्मिश्रण है एक मुसलमान क्या, हजारों वर्षों से पता नहीं कितने लोग आये जिन्होंने यहां आकर हमारी संस्कृति को उन्नत करने में योगदान दिया है। इसका विवरण इतिहास में मौजूद है। लेकिन आज उसको अलग नहीं किया जा सकता है। आज हम नहीं जानते कि हमारे मुसलमान कितने मंगोल है, मैं नहीं जानता कितने शक हैं, कितने हूण हैं। जब हम यह नहीं जानते हैं तो फिर कितने मुसलमान हैं यह जानने की कोई जरूरत नहीं है। किसी के चहरे पर यह नाम लिखे नहीं होते, किसी के चेहरे पर इस बात का आभास नहीं होना चाहिये और जैसा हमारा देश है, जो हमारी महान परम्पराएं हैं, उनको यदि हम अक्षुण्ण बनाये रखना चाहते हैं, उस परम्परा पर किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें अपने दूसरे साथियों से, दूसरे भाइयों का लिहाज अपने से ज्यादा करना होगा।

3 P.M.

मैं समझता हूं कि यह बात सब के लिये समान रूप से लागू होती है। इसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता है। इसमें किसी को कोई विशेष स्थान मिले, यह नहीं हो सकता। श्रीमन्, महानता की परिभाषा जो पढ़े-लिखों ने की है, वह क्या है ? ओपननैस आफ माइंड, ग्रेटनेस आफ हार्ट। यह दो गुण जिनमें होते हैं, वही महान होते हैं। केवल शब्द बड़े हो, नाम बड़ा हो, उससे कोई महान नहीं होता है। जिसका दिल और दिमाग खुला होता है और खुले दिल और दिमाग से सोचता है, आने वाली नई घटनाओं से एडजस्ट करता है, जो परिवर्तन होता है, उसको स्वीकार करता है और उसको स्वीकार कर जो बा चुका है उसको भी स्वीकार करके और वर्तमान परिस्थितियों में आगे के बारे में सोचता है, वही तो बड़ा है। तो इस प्रकार से यदि इस यूनिवर्सिटी की परिभाषा में इन शब्दों को जोड़ दिया जाए, तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि इसमें भावना की दृष्टि से कोई आपत्ति की बात नहीं है केवल इसी बात से कि किसी के दिल को चोट लगती है, तो इसको स्वीकार करने में हमें कोई एतराज नहीं है। यदि मैं यह कहूंगा कि हमें चोट लगती है, तो उनके शब्दों को सुन कर हमें भी चोट लगती है। इतनी सी बात के लिये चोट नहीं लगनी चाहिये। जब हम साथ बैठे हैं, साथ जीना है, साथ मरना है, इस देश की उन्नति में हमारी उन्नति है, इस देश की अवनति में हमारी अवनति है, तो फिर हम एक दूसरे को छोटी-छोटी बातों को बहुत ज्यादा गम्भीरता से नहीं ले सकते। इसमें कुछ बातें अपने आप ही सोचनी पड़ेगी। परन्तु कानून की मन्शा से मैं समझता हूं कि यह शब्द इसमें रिडन्डेन्ट हैं।

इन शब्दों से कोई विशेष अधिकार इस एक्ट के अन्तर्गत मिल जायगा, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। यदि यह शब्द जुड़ गये तो इससे कोई नई बात होगी, इस एक्ट के स्वरूप में कोई ऐसी चीज होगी जिससे इस देश के मुसलमानों को कोई विशेषाधिकार प्राप्त हो जायेंगे, ऐसा इस अमेंडमेंट से होने वाला नहीं है।

तो जब किसी अमेंडमेंट का परिणाम केवल शब्दावली में, केवल एक सेक्शन में कुछ शब्द और जोड़ दें जिससे उस कानून को लागू करने में कोई असर न हो, कोई अन्तर न पड़ता हो, तो मैं समझता हूं कि कानून में इस प्रकार के शब्दों को आवश्यक नहीं समझा जा सकता। उनकी वैसे भी बहुत आवश्यकता नहीं है। केवल भावनाओं के आधार पर यदि विचार करना हो, तो मैं समझता हूं

कि हमारे हाउस के सभी सदस्य एक ही स्वर से एक ही बात कहेंगे, कोई दो बात नहीं हो सकती। लेकिन हमारी कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए। हम कहते तो ठीक हैं, लेकिन उसे करने का सवाल होता है। यदि हर वर्ग अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा कि इसमें हमको सन्तोष मिलता है, इसलिए यह बात होनी चाहिए। भले ही इसका उपयुक्तता कुछ न हो। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई भी तर्क किसी भी कार्नर से क्यों न आए वह तर्क बहुत गम्भीर नहीं माना जा सकता। उसको हम बहुत ज्यादा ठोस भी नहीं मान सकते। अदालत में तो जब कानून बनता है, तो कानून के तरीके से, उसकी भाषा से और जो कानून के इम्प्लीकेशन्स हैं, उनके परिणाम हैं, उनको मद्देनजर रख कर ही बनाया जाता है। इसलिए यह जो केवल शब्दों का संशोधन है, यदि इसमें से भावनाओं की बात निकाल दी जाए तो इस यूनिवर्सिटी की भावना में इसको जोड़ना कानून के लिए जरूरी नहीं है।

इसलिए मैं प्रस्तावक महोदय से इस संशोधन के बारे में यह निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में जरा पुनः विचार करें कि क्या इसकी नितान्त आवश्यकता है कि इसके बिना यह एक अधूरा है, या इसके बिना कोई अधिकारों पर कहीं कमी पड़ती है, तब तो इसको शामिल करने में कोई ऐतराज नहीं है, यदि उनको लगता है कि यह शब्द रिडेन्डेन्ट हैं, इन शब्दों को जोड़ने से कोई अतिरिक्त लाभ होने वाला नहीं है, तो वे स्वयं इस पर विचार करेंगे। एक क्लाज 5 (बी) को डिलीट करने की भी बात इसमें है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को पढ़ कर सुना दूं। क्लाज 5(ii) जो है, वह यह है कि :

"(a) to promote Oriental and Islamic studies and give instruction in Muslim theology and religion, and to impart moral and physical training;

(b) to promote the study of the religious philosophy and culture of India."

इसको डिलीट करने की मांग पर, मैं समझता हूं, जो बात मैंने कही विनम्रता के साथ, यदि उन विचारों से हम सहमत हैं तो फिर इसको डिलीट करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक शिक्षा प्रधान संस्था है जिसमें शिक्षा दी जाती है और मैं समझता हूं शिक्षा किसी धर्म तक सीमित नहीं हो सकती, यदि हम शिक्षा ही प्राप्त करना चाहते हैं, उसको किसी एक विशेष कार्नर में संकुचित करके, संकीर्ण करके, नहीं रख सकते। आखिर शिक्षा का मतलब तो होता है समान रूप से, विकसित रूप से, जब हम शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों का निर्माण करना चाहते हैं, हम उससे पहले अपने विद्यार्थियों का जीवन निर्माण करना चाहते हैं, उनके मस्तिष्क का विकास करना चाहते हैं और इतना विकास करना चाहते हैं कि मानव ही नहीं, महा मानव और अति मानव बन सकें, तो फिर आप विचार करिए यदि हम स्वयं ही अपनी यूनिवर्सिटीज को नीचे की तरफ ले जाना चाहें तो कहां तक अच्छा लगेगा। आप जानते हैं, हमारे देश में जातियां हैं, लेकिन क्या कोई महापुरुष किसी जाति विशेष के छोटे दायरे में आबद्ध किया जा सकता है? क्या किसी महापुरुष को एक काल विशेष में आबद्ध कर सकते हैं? मैं समझता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए और अगर कोई इस प्रकार की कोशिश करे तो यह न केवल ऐसा करने वालों के लिए घातक है बल्कि उनकी महानता में भी आंच और आपत्ति लाने वाली चीज होती है। तो जब सिविलिजेशन, और खास कर इंडियन सिविलिजेशन, की बात यहां कही गई है, इण्डियन कल्चर की बात कही गई है, तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम कल्चर उससे कुछ भिन्न नहीं है। आज जब हम इण्डियन कल्चर की बात करते हैं तो क्या उसमें मुस्लिम कल्चर शामिल नहीं है? यदि कोई ऐसा मानता है तो वह गलत है, निराधार है, उसको मानने का कोई कारण नहीं है। जब जब हम भारतीयता की और भारत की बात करते हैं, अपनी

[श्री हरी शंकर भाभड़]

संस्कृति की बात करते हैं, तो इस देश के समग्र जितने भी लोगों ने इसकी संस्कृति को बढ़ाने में योगदान किया है, वह सब इसमें शामिल हैं, उनको अलग किया ही नहीं जा सकता । तो ऐसी स्थिति में इसका मैं विरोध करता हूं कि यह सेक्शन 5(बी) का जो डिलीशन करने की मांग की गई है; मेरी समझ में इसका कोई औचित्य नहीं है और इतना ही नहीं, हो सकता है इससे, जिस भावना के साथ यह संशोधन लाया गया है बिल के रूप में उस भावना से ही उस पर आघात होगा । जहां एक ओर हम स्वयं चाहते हैं कि हमारे कामों से ऐसा लगे कि हमारा कोई वर्ग, हमारा कोई भाई नाराज न हो, उनको भी सन्तुष्टि मिले, तो यह सबके लिए समान हो । अगर इस को हटाने से औरों के दिल में चोट लगती है, तो हम को इसका भी विचार करना पड़ेगा कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं उसका परिणाम ऐसा होना नहीं चाहिए जो किसी के भी दिल को आघात पहुंचाए, चोट पहुंचाए और जिससे किसी के भी अधिकार पर अतिक्रमण हो । मैं कहता हूं, यह क्लाज 5(बी) को डिलीट करने से दूसरों के अधिकार पर आपत्ति आ रही है । इसमें भावना का सवाल नहीं है, कानूनी आपत्ति आ रही है । आप किसी भी व्यक्ति को शिक्षण संस्था में एक विशेष धर्म की शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते । सेकुलरिज्म का मतलब एण्टी रिलीजन नहीं है, धर्म विरोधी नहीं है। उसका मतलब तो स्पष्ट यह है कि हमारे यहां सभी धर्मों को समान रूप से विकसित करने के समान अवसर प्राप्त होते हैं और अपनी विशेष रुचि के अनुसार किसी धर्म में भाग लेने से रोका नहीं जाएगा, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जाएगा । अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यदि भारत की सारी संस्कृति के अनुसार पढ़ायी की जाती है उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और यदि कोई उसमें आपत्ति करता है तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि इस ऐक्ट का जो स्वरूप है, जो क्षेत्राधिकार है, उसको कम करना है जो कि कदापि उचित नहीं है । उसके लिए कोई औचित्य नहीं है इसलिए सेक्शन 5(बी) को डिलीट करने का जो संशोधन यहां पर प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं और प्रस्तावक महोदय से, जिन्होंने बिल पेश किया है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे इस पर इतना आग्रह नहीं करें अन्यथा जिस मकसद से, जिस मतलब से, वे इस बिल को लेकर आए हैं वह अपने आप में फ्रस्ट्रेट होगा, उस पर इसका बुरा असर पड़ेगा । इसलिए हमारे इस निवेदन पर वह ध्यान देंगे । इतना कह कर मैं धन्यवाद देता हूं ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Some hon. Members who had already spoken on this motion, want to speak again because some amendments have been brought in. I would suggest that they may kindly do so when the clauses and amendments are under discussion but not at this stage. After Shri Triloki Singh has replied to the debate, we will put the motion to vote.

SHRI TRILOKI SINGH: Mr. Deputy Chairman, Sir, I am deeply obliged to you and those Members of this august House who have participated in this debate and made useful suggestions.

[The Vice-Chairman (Shri Arvind Ganesh Kulkarni) in the Chair.]

Sir, the importance, the main thrust of the Bill as I had said in the very beginning, was that the Aligarh Muslim University should be given the status of a minority character in terms of the provisions of Article 30 of our Constitution. The hon. Minister of Education who intervened in the debate, said that the Aligarh Muslim University was an institution of national importance and that it was in the Union List. Sir, had it not been in the Union List, I would not have moved this Amendment Bill. And it is not that after the Constitution of 1950 came into force that the Aligarh Muslim University became a Union

subject; it was Central subject at the time of 1935 Act also.

Now, what I mean by bringing in this Bill is that it was established at the instance of the Muslims of India. The hon. Minister of Education and some other Members took objection to this suggestion. I would like, Sir, with your permission to quote the speech of the hon. Minister himself which he made while intervening in this debate on the 1st December, 1978. It is at page 321:

> "... but certainly the Muslims were the promoters. They took keen interest; it was established at their instance no doubt."

This is what the hon. Minister himself admits. He said that much while intervening in this debate. My Bill seeks only to import this idea that it was established at the instance of the Muslims of India. Nothing else. No difference. Interpret it in whatever manner you like. Apply any authority whether it is Maxwell or Harwell. Simple interpretation. There is no disagreement between what the Minister of Education substantially accepted and what my Bill seeks to do.

Sir, the whole trouble arose with the Supreme Court judgement in the Aziz Pasha case. Why? The Supreme Court held that it was not an institution established by the Muslims of India and that, therefore, it cannot be given a minority character in terms of Article 30 of the Constitution. Before that nobody thought that it was not a minority institution, leave aside anything. The word "Muslim" itself is in the name of the University, it was rightly pointed by the hon. Members from that side a few minutes back. Why Muslim? There is the Lucknow University, the Dacca University, the Calcutta University, the Bombay University, but here in this case it is the Muslim University. And then Sir, nobody denied that the idea of a Muslim University arose from the Muslims and not the Britishers.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh): Just a clarification There is a Jat College, there is a Rajput College and so on. Then what do they signify?

SHRI TRILOKI SINGH: It signifies that it has been established by Jats.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: And those institutions should have caste character or Kayasth character (*Interruptions*).

SHRI TRILOKI SINGH: Just listen The Jats may be there in a minority just as the Hindus are in a minority in the Punjab State and the DAV complex in the Punjab Province has the status of a minority institution The Christians are in a minority in Kerala. Therefore, institutions established by the Christians in Kerala according to the judgement of the Supreme Court, are also minority institutions. Therefore, through you Sir, I would like to draw the attention of the hon. Member to the fact that minorities may be linguistic or religious. But "Jat" as such is not a religion. Hinduism is a religion Parsi is a religion, Sikhism is a religion, Islam is a religion...

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK (Orissa): On a point of clarification

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Let him finish.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK I am on that point only. I am not opposing.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI) Has he completed his reply? (*Interruptions*) Please take your seat.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK Institutions not of the minorities but for the minorities. Institutions cannot be of a minority character. A college or university or school may be for particular community or a group of people. But that does not take away

[Shri Harekrushna Mallick]

the national character of the institution. Everything that is in India must be Indian basically.

SHRI TRILOKI SINGH: With your permission, Sir... (*Interruptions*)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Bihar): On a point of order.

SHRI TRILOKI SINGH: I would like most humbly to submit, if I am wrong on facts...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Triloki Singhji, please take your seat. He is on a point of order.

श्री शिव चन्द्र झा : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इनका संशोधन हम लोगों के बीच में घूम चुका है । इन्होंने अपने ही विधेयक पर संशोधन मूव किया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो बोलने के लिये खड़े हुए है अपना संशोधन मूव करने के लिये खड़े हुए हैं या जो बहस हुई है उसका जवाब देने के लिये खड़े हुए हैं । यह इसलिये कहना चाहता हूं कि अगर अब यह संशोधन मूव नहीं कर रहे हैं तो जब यह संशोधन मूव करेंगे तब फिर यह बोलने के लिये खड़े होंगे । मेरी यह अनुरोध है कि पहले यह अपना संशोधन मूव कर लें और उस पर जिन्होंने बोलना हो वह बोल लें तब यह कंपरिहेंसिव जवाब दे दें ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी): वह माथुर साहब का जवाब दे रहे थे In the meantime that Doctor stood up. You go ahead, Mr. Triloki Singh.

श्री शिव चन्द्र झा : मेरा यह कहना है कि पहले वह अपना अमेंडमेंट मूव कर लें और फिर आखिर में जवाब दे दें ।

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: On a point of clarification.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): He is replying to the debate on the motion of consideration. So you have to take your seat. He will continue.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: He has not moved the amendments. We have something to say on the amendments.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): That stage has not come, my dear friend.

SHRI TRILOKI SINGH: At the moment, the matter is under the consideration of the House...

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : वाइस चेयरमैन साहब, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । क्योंकि हम जब सदन में आए और आने के साथ ही हम को यह एक अमेंडमेंट दी गई । क्योंकि उनका अपना अमेंडमेंट था और उसी के ऊपर उन्होंने अमेंडमेंट दी है तो मैं उसी रोशनी में बात कहना चाहता हूं कि जो मेरा सारा उपन्यास है वह जो अमेंडमेंट हाथ में है इस पर है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने अपना अमेंडमेंट पेश किया है या नहीं । मैं यह क्लेरिफिकेशन चाहता हूं कि यह अमेंडमेंट पेश किया गया है या नहीं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): He is replying to the main debate. Then we will come to the amendments.

श्री त्रिलोकी सिंह : माननीय, माननीय सदस्यों की सूचना के लिये मैं इतना अर्ज कर देना चाहता हूं कि अभी केवल इस बात पर विचार हो रहा है कि इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर विचार किया जाए । अभी तरमीम या संशोधन पर विचार नहीं हो रहा है । माननीय सदस्य अगर इतना समझ कर चलें कि जो कुछ मैं अर्ज कर रहा हूं उससे उनकी समझ में और मेरे कहने में कोई फर्क नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं पैदा होगी ।

I was just telling the House that there is no difference between what this Bill seeks to do and what the honourable Minister when he intervened in the debate said, that there is no doubt that it was established at the instance of the Muslims of India. Now as I said a minute back, the whole difficulty arose out of a judgement of the Supreme Court. Now, the judgment of a High Court or the Supreme Court is of two kinds. One is a finding of fact and the other is of Law. In this case the Supreme Court's finding is of law. And a finding of law can always be changed by Parliament, by the House, or by the Legislature of a State if it relates to a State subject. Therefore, on that ground also the argument advanced by the honourable Minister of Education that the Supreme Court had given a judgment and that it was a finding of fact... (*Interruption*) My honourable friend, Mr. Sankar Ghose, who is not present here now, had dealt with that point in great detail. There is another point which is very well known. It is well-known law—and the Minister knows coming as he does from a very eminent solicitor's firm—which says, it is the law of contract, and according to Cooley and other authorities, if anything has been brought about as a result of a contract between two parties, then it cannot be changed without reference to the other party. May I know if there is anybody in this House or outside who denies the fact that the Aligarh Muslim University came into being as a result of an agreement entered into between the Secretary of State for India on the one side and the Aligarh Muslim University Foundation Committee and the Mohammadan Anglo Oriental College on the other side? Sir, read the Preamble itself. It is written there, this institution..

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: No. no.

SHRI TRILOKI SINGH: My friend who is sitting just next to him drew my attention in particular to the history. Let him not deny that it was the Secretary of State for India who ruled this country right up to 1947..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): You ignore his remarks.

SHRI TRILOKI SINGH: You are SHEIKI (Andhraa Pradesh): At that brought about as a result of ....

SHRI GHOUSE MOHIUDDIN SHEIKH (Andhra Pradesh): At that time he was a *bachcha.*

SHRI TRILOKI SINGH: Or he might not have been born even....

SHRIMATI HAMIDA HABIBULLAH: He was a *bachcha.*

SHRI TRILOKI SINGH: Sir, nobody denies, I don't think anybody present here denies, that under the Constitution, under Article 30, the minorities have a right to establish and maintain an institution of their choice. The Minister at great length went into the history of the Aligarh Muslim University. His main point was that non-Muslims were also educated in the Aligarh Muslim University, that there were non-muslim teachers, that there was a non-Muslim principal. All right. But if he had read the provision of the Constitution itself carefully, it is incumbent upon any institution which seeks recognition from the Government, whether it is a Christian institution or a Hindu institution or any other institution, that it will be open to students of all sections. With regard to teachers also not that only Muslims shall be appointed as teachers. In the case of the Aligarh Muslim University right up to 1951, I would like to draw the attention of the houourable Minister, the management vested in a court which consisted exclusively of Muslims. And then so much stress has been laid upon history. I would like to quote from what the

[Shri Triloki Singh]

Education Member wrote to the Governor-General-in-Council on 16-5-1911;

> "I have had four long sittings with the Mohammadan delegate and I think that we have come to a satisfactory working arrangement, but we ought to regularise the position now. We are really, in effect, committing ourselves."

Then, in 1911 education was a provincial subject. The Education Member wrote to the Lt. Governor of Uttar Pradesh to obtain his consent on 3rd June, 1911, in the following words:

> "Since the Muslim community is united in demanding a university, I, therefore realise that the Muslim University will have to be allowed."

I want a simple, grammatical meaning of what I have put before the House, namely, "I, therefore, realise that the Muslim university shall have to be allowed."

In the despatch sent by the Governor-General in Council to the Secretary of State for India on 27th June. 1911, he said thus:

> "Complete confidence of the Muslim community—If your Lordship agrees, we propose to enter into negotiations with the Committee with a view to framing detailed, practical proposals which we can lay before the Lordship for approval."

What more can one want, so far as historical proof is concerned? I refer you to what I quoted in my opening speech. It is not good to quote oneself. It relates to the speech of the Governor-General-in-Council when this Bill finally came for passage before the Imperial Assembly in September, 1920. The Governor-General in Council himself came to preside over it. Ordinarily, the Home Member used to preside over the meetings of the Imperial Legislative Council. The Governor-General-in-Council himself joined in offering congratulations to the entire Muslim community and said:

> "This is going to be a historical decision".

Sir Surendranath Banerjee of hallowed memory also did the same thing. My friend, the Education Minister knows that he was known as uncrowned king of Bengal for more than a quarter century. He was supposed to be the best orator that India has ever had. Sir Surendranath Banerjee, while speaking and taking part in the Aligarh Muslim University Bill in 1920, said as follows:

> "Sir, speaking as a representative of the Hindu community, we desire to welcome the Bill which has been introduced and also to congratulate the hon. Member in charge of it (Sir Mohammed Shafi was the Member) on the admirable speech which he has made in introducing it. That, I think, represents the attitude of the Hindu community. This University is to be a unitary and residential University, and it is to represent an advance upon the type of Universities, which have been established in Dacca and in Banaras. All that is welcome, not only from the Muslim, but also from the general and the larger standpoint."

This is what Sir Surendranath Banerjee said. Then I would like to say one more thing. At the very beginning when the foundation stone of the Muhammedan Anglo-Oriental College was to be laid, Lord Lytton went there to lay the foundation stone. What he said was published in the Gazette also. He said:

> "This devoted band of Muslim workers held a series of meetings, the last of which took place on 15th April 1872 in which it was

decided to establish a Muhammadan College, and on 12th May that year, a society called 'The Muhammedan Anglo-Oriental College Fund Committee' was started for collecting subscriptions for the realization of that end."

Then Sir Syed said:—

"Looking at the difficulties which stood in our way and the success which has already been achieved, we do not doubt that we shall continue to receive, even in larger measure, both from the English Government and from our own countrymen, that liberal support which has furthered our scheme, so that from the seed which we sow today there may spring up a mighty tree whose branches, like those of the Banyan of the soil, shall in their turn strike firm roots into the earth and themselves send forth new and vigorous saplings that this College may expand into a University whose sons shall go forth throughout the length and breadth of the land to preach the gospel of free enquiry, of large-hearted toleration, and of pure morality."

May I know from the hon. Minister whether the idea to establish a university of its own had occurred to anybody as long back as 1872? It was at British initiative, at the initiative of the British Government, whether it was the policy envisaged in 1884 by Sir Charles Wood, Secretary of State or Lord Curzon in 1902, and it is they who thought of establishing a university and it was the Saddler Commission, on whose recommendation the Dacca University was founded and the idea of residential Universities at Allahabad and Lucknow cropped up. Is there any Indian who can claim, is there anybody who can claim, that he has done anything in this regard? These are all facts of history which nobody can deny. Therefore, Sir, the argument that non-Muslims were educated from the very beginning and the first graduate of the MAO College was not a Muslim and, therefore, it is not a Muslim institution or the argument that the teachers were non-Muslims or the first Principal was an Englishman and, therefore, it is not a minority institution, is not correct and these arguments do not hold water even for a second. My submission, Sir, is this: I am not going to take long. I hope that the honourable Members know more about it than myself.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: How?

SHRI TRILOKI SINGH: Because I take them to be intelligent people, to be well-informed people, to be well-versed in the parliamentary practices, and know the history of their country. I do not think, Sir, that and I am not prepared to believe even for a second—that any honourable Member of this House is so ignorant of the history of India during the last hundred years or so. At least I am not prepared to believe it. Even if some were to admit that it is so, I will only take it as an argument just to meet my argument. Sir, I will not take long. One Member has drawn attention to section 5(2)(b). All I would like to say is this: I would like to draw his attention to the words "to promote the study of the religions, civilization and culture of India". This provision does not find a place in any Act, Sir, of any University in this country and it was for the first time in 1972 that it was put in the Aligarh Muslim University Act. Nothing like that is there in the Banaras Hindu University or in the Madras University. I am not against the study of the religions or civilization or culture. But why single out the Aligarh Muslim University alone? If the honourable Members think that it should be so, then I have no objection. My idea was that with this there might arise some problems. You know that the Muslims do not believe in idolatry. Once you open a department in the University of Aligarh or in the Delhi University, then there is bound to be

[Shri Triloki Singh]

clashes between the students and the teachers. But, if the honourable Members think that it is good, then I would like the honourable Minister to put in such a provision even in the Delhi University Act and the Banaras Hindu University Act.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Yes, I welcome it.

SHRI TRILOKI SINGH: I have no objection to that. In the very beginning I had said that all that I wanted was that it should be made explicit, clear, unambiguous, that the Aligarh Muslim University was founded by the Muslims of India. The mere fact that under section 6 of the Aligarh Muslim University Act the degrees become recognisable, that it is only because of law, does not mean much. If that is so, then take the D.A.V. College, Amritsar. The degrees awarded by the D.A.V. College are recognizable only because it is affiliated to the Guru Nanak University or the Punjab University and the degree awarded by the Christian College, Lucknow, is recognised only because the Christian College is affiliated to the Lucknow University. Therefore, Sir, I know it and I know the history of the national institutions, and my friend the honourable Education Minister, should know the educational institutions established by Raja Rishikesh Lowe in 1907 in Bengal, then the University in Santiniketan, then the Bihar Vidyapith, the Kashi Vidyapith, the Tilak School of Politics, the Gujarat Vidyapith and many others. None of the degrees awarded by these institutions were recognised in pre-independence days, because they had not been established under an Act. For the degree to be recognised, an Act of a Legislature whether it is Parliament or a State Legislature, is necessary. The very fact that the Mohammedan Anglo-Oriental College Degree was recognised by the Government, it was affiliated to the Allahabad. University does not mean that it was not a minority institution. That is also the view of the Supreme Court. I am not going to tell this august House that the mere fact that a degree awarded by a College has to be recognised by Government by a statute does not take away the minority character of the institution.

Therefore, Sir, with these words I commend to the House that the Bill moved by me, the Aligarh Muslim University (Amendment) Bill, 1977, be taken into consideration.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): The question is:

"That the Bill further to amend the Aligarh Muslim University Act, 1920, be taken into consideration."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA): We want Division... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): All right... (*Interruptions*)

(*Division Bell*)

DR. RAM KRIPAL SINHA: We don't want division. Let it be by voice vote.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): The question is:

"That the Bill further to amend the Aligarh Muslim University Act, 1920, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): We shall now take up clause by clause consideration of the Bill. There are three amendments to clause 2.

Clause 2—Amendment of section 2

SHRI TRILOKI SINGH: Sir, I move amendment No. 3 only. I do

not want to move amendment Nos. 4 and 5. Sir, I move:

3. "That at page 1, *for* clause 2, the following clause be substituted, namely:—

'2. In section 2 of the Aligarh Muslim University Act, 1920 (hereinafter referred to as the principal Act), for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) 'University' means the educational institution of their choice established by the Muslims of India which originated as the Mohammadan Anglo-Oriental College, Aligarh and which was subsequently incorporated as Aligarh Muslim University." '".

Sir, I need not say anything about my amendment.

The motion was proposed.

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): Sir, may I be permitted to make my submission on this amendment to clause 2? Sir, the very fact that the hon. Mover of this Bill has moved this amendment clearly shows that he does not know his mind. At the beginning he said that the University has been established at the instance of the Muslims of India, and he has referred to my speech where I had conceded that point. But I had opposed that Bill at that time because the hon. Mover made it clear that he wants to confer the minority character to this institution. I have referred to the Supreme Court's judgment which has agreed that the institution was established primarily at the instance of the Muslims of India; the Muslims could have established a separate University without the involvement of the Legislature of the day. Whether the degree is recognised by the Government or not is a different question. We have the Gurkul Kangri Viswavidyalaya. Later on, it was adopted as a deemed university under the present University Grants Commission Act. Similarly, the hon. Mover has referred to the Visva-Bharati. Whether the degree is recognised or not is different matter. That does not mean that the university cannot be established. Recognition of a degree does not depend on the Government only. A degree may be recognised by many other institutions, by the public at large. So, the Supreme Court held that the Muslims in those days could have established a University of their own but did not establish such University. And the Supreme Court ultimately came to the conclusion that it was the Central Legislature which brought into existence the Aligarh Muslim University and must be held to have established it. Therefore, what the hon. Mover now by introducing the amendment tries to impress upon is that the institution was established by the Muslims of India but later on it was incorporated into the Act. What was established by the Muslims of India was the Mohammadan Anglo-Oriental College. But that College was dissolved. It was not that it was merged or transformed into a University. The college itself was dissolved.

Sir, if you look at the Preamble of the Act of 1920, which was moved by the then Education Member, Mr. Mohammad Shafi, who was one of the prime-movers for the establishment of a Muslim University, you will find that he has indicated in the Preamble that "whereas it is expedient to establish and incorporate a teaching and residential Muslim Univtrsity at Aligarh and to dissolve establish and incorporate a tracking and residential Muslim University at Aligarh and to dissolve this Society registered under the Societies" registered under the Societies" Registration Act, 1960, which was originally known as the Mohammadan Anglo Oriental College". Therefore, Jana Mohammed Staff actually wanted to tell before the legislature of the day that he was going to establish a new university and the old college was dissolved. It is not that there was a merger and

[Dr. Pratap Chandra Chunder]

was transformed into a University like that. What he wanted to place before the legislature of the day is that he was going to recommend the establishment of a Muslim University and that could be done only by the legislature. That is what the Supreme Court has said. The hon. Member has referred to the fact that there is a sort of agreement between a section of the Muslims and the Government. Now, Sir, we all know what is meant by a contract. Contract is an agreement enforceable by law. Now, could at any moment, a section of the Muslims, who were interested in the establishment of a Muslim University, have sued the Government of the day in those days, if there were certain variations in the Aligarh Muslim University Act. In fact, several variations had taken place but nobody had thought of filing a suit against the Government for breach of contract.

In 1951 very important changes have been introduced in the Act, when my esteemed predecessor, the great leader, Maulana Abul Kalam Azad was the Education Minister. Similarly, later on, twice this Act had been amended. When in 1965-66 some changes were made, some members of the minority community, Mr. Aziz Bhasha and others, wanted to challenge the competence of Parliament. Now, the whole question is what are we going to achieve by the so-called conferment of the minority status. It does not mean that Parliament cannot pass any legislation in respect of this Muslim University. Let us be very practical about it.

Sir, I am not yielding to anybody in our concern for the glory of Islamic culture in India. India has a composite culture. It does not belong to Hindus only. It also belongs to Muslims and various other communities. That does not mean that to placate some feeling which is there—I concede that this feeling is there—and to satisfy certain emotions, this august House, the House of Elders, will do something which will try to dis-establish established facts recognised by the Supreme Court of India. That is my humble submission. By bringing this amendment, Sir, the whole of the established fact is sought to be disestablished. Of course, the hon. Members on the other side have got the majority. They can try to pass it. But, I know, Sir, that the effort that they are trying to make, will not succeed. There is no parallelism between a Christian college or a Muslim college on the one hand, and a Muslim university, which is established by an Act of Legislature or by an Act of Parliament. This House or this Parliament cannot ban the power of future Parliaments because that type of effort will not succeed. Therefore, the whole concept of minority character does not hold any water. This is my humble submission. That is why, Sir, I am opposing this amendment. My most humble request to the hon. Mover is to reconsider this matter. I have already told this House that I have brought forward a substantive Bill in the Lok Sabha. I could not get time to do it earlier because of various other complications and this Bill will be taken up during this session of Parliament, where the old historic character of the university will be sought to be returned and we are making an effort in that behalf. The Bill had been considered by the Minorities Commission also. Sir, the Minorities Commission has also suggeted certain amendments and we are going to accept most of these amendments keeping in view the decision of the Supreme Court. So, I, once more, appeal to the hon. Member, who has moved this Bill, to consider the implications of what he is going to do. I am quite one with him in his concern for the welfare of minorities. It is this Government which has for the first time set up the Minorities Commission. This Government has placed on the Table of the House a copy of the Gujral Committee's Report on Urdu and we are trying to do whatever is possible in our power. But whatever is not possible under the law, certainly we cannot do that. This is my humble submission.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, . . .

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI (Uttar Pradesh): Sir, the Minister has already replied.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: I am very much disappointed to hear the reply given by the hon. Education Minister. May I remind him that in Calcutta there was a college known as Islamia College? In our eagerness to show that we are really secular, we did away with the name Islamia College and gave the name of Central Calcutta College as if there is no Central Calcutta College. It only proved our apathy to the rights of the minorities. Have we done away with the name of BHU? We have not and the university is still there. When we did a damage to the concept of Aligarh Muslim University, a proud place in our educational system, we have no right to take away the minority character from that institution. We were wrong when we passed that legislation in the past. Let us admit. And here are the Janata Party Members who took full advantage of our mistake in passing that legislation when we were in the Government last. Here, when Triloki Babu, our hon. friend moved a Resolution just to repair the damage that we have done, the Education Minister ought to have welcomed it. He ought to have said that he accepts the suggestion and that a formal official Bill would be brought forthwith. Instead of that, he is opposing it. We are sorry to see this attitude and we wholeheartedly support the Bill as well as the amendment by Trilokiji.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, I rise to fully support the amendment and I am glad that I have a chance...

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: You always have a chance.

SHRI BHUPESH GUPTA: In fact, I was somewhere and I came rushing here...

SHRI KALP NATH RAI (Uttar Pradesh): I also support the amendment.

SHRI BHUPESH GUPTA: The reply of our hon. friend, Dr. Chunder has given a doubt whether, if he read his speech forgetting for a while the RSS, it would satisfy him. I have my doubt...

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: Not CIA.

SHRI BHUPESH GUPTA: I have better idea. It is only the acknowledgment of a historical fact, acknowledgment of an undisputed historical fact. What is wrong there if it is included? Therefore, Sir, on that ground he should accept it.

Secondly, as Shrimati Mukhopadhyay has rightly pointed out, why this discrimination against the Aligarh Muslim University? Why? Others are there carrying this kind of a name and definition and all the rest of it. There is no justification whatsoever.

Besides, Sir, today there is an offensive against the secular principles, offensive against the minorities, their cause and their rights. Can we say we have given protection to them in full measure? Why did we bring in the Minorities Commission? Sir, I am connected with the Committee which has been appointed by the Prime Minister to go into the question of communalism and make recommendations to the Government. Some Chief Ministers are there. Sir, at the meeting of the opposition leaders with the Chief Ministers it was pointed out that the recommendations of the Minorities Commission, the interim recommendations, with regard to Aligarh disturbances last year, were not implemented. The recommendation of the Minorities Commission was that the PAC forces should be withdrawn. It was found that this recommendation had not been implemented like many other recommendations. Now, they are being implemented. Sir, I do not wish to take much of your time. I think we should wholeheartedly support it. I think, my friends on the other side should also support

[Shri Bhupesh Gupta]

it. As far as Mr. Chunder is concerned, I do not know what kind of amendment I should move to save him from the clutches of the RSS.

श्री शिव चन्द्र झा : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मूवर ने पेश किया है उससे कुछ बोलने के लिये मद में आ जाता है कि जरूर ही बोलूं । इन्होंने एक माने में सुधार किया है अपने विधेयक में । पहले इनका था

"at the instance of Muslims of India"

जिसको लेकर यहां हल्ला हुआ । मैं भी बोला था और पुरजोर इसका विरोध किया था । मैंने कहा था कि इन शब्दों से इसका साम्प्रदायिक रूप हो जाता है और एक आवाज से सारे सदन में उस सन्टेंस का

"which shall be deemed to have been established at the instance of Muslims of India"

विरोध किया गया था । इन्होंने पुनर्विचार किया और अब उसको हटा रहे हैं । एक कहावत है कि देर आयद दुरुस्त आयद । लेकिन उसकी जगह जो ला रहे हैं वह भी इतना ही खराब है । यह बिल्कुल साफ है कि यह भी उतना ही खराब है जितना पहला था । जो ला रहे हैं वह यह है

"established by the Muslims of India"

यह ठीक है कि पुराने से थोड़ा सा परिवर्तन है लेकिन कोई बुनियादी परिवर्तन इस संशोधन में नहीं है और इस संशोधन से फिर विधेयक का वही रूप हो जाता है—साम्प्रदायिक रूप जो पहले होता था । (*Time bell rings*) मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं । मैं साफ कहना चाहता हूं कि बी० एच० यू० है बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी । अगर कोई कह दे कि बी० एच० यू०

"by the Hindus of India, it shall be established"

तो इसका कोई मतलब होगा । अगर कोई बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में संशोधन ला दे कि "by the Hindus of India, तो कोई सेंस होगा । मैं कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वह सर सैयद अहमद खान की मेहनत से, उनकी कोशिशों से बनाई गई थी और मुसलमानों का उसमें कोई हाथ नहीं था । लेकिन उनका नाम. . .

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): I have my limitations. I cannot forbid the Members from saying whatever they want. Let them say whatever they want.

श्री शिव चन्द्र झा : मुस्लिम का नाम देने से वही रूप हो जाता है । अब सवाल यह आता है इसके पीछे दृष्टिकोण क्या था । इसके पीछे सर सैयद अहमद खान का दृष्टिकोण मार्डन था । वह माडर्न एजुकेशन लाना चाहते थे, यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे इसीलिये उन्होंने युनिवर्सिटी बनाई । पहले यह इन्टर कालेज था जिसका नाम इन्होंने बदल दिया था । यह एक कहानी है । इसलिये यदि इनका पुराना दृष्टिकोण है तो उनका ही नाम रखें । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त हम यदि विश्वविद्यालय पर गौर करते हैं तो उसके नाम को एक दूसरे रूप में सोचने की जरूरत हो जाती है । मैं एक उदाहरण देता हूं. . .

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी) : उदाहरण बहुत हो गये हैं ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं केवल एक ही उदाहरण देता हूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कालेज है जिसका नाम पहले जी०बी०बी० कालेज था । जब देश आजाद हुआ तो बिहार की बागडोर श्री कृष्ण सिंह नारायण सिंह के हाथ में आई । तब उन्होंने यह देखा कि यह नामकरण आज के वातावरण में ठीक नहीं है

इसलिये उन्होंने इसका नाम बदल दिया लेकिन जिस आदमी ने कालेज बनाया ....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Jha, please conclude. I am calling the next speaker.

श्री शिव चन्द्र झा : इस तरह से यदि आप को नामकरण बदलना है तो आज के वक्त में पहले तो आप अलीगढ़ मुस्लिम को हटा कर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी रखें और अगर आप नाम ही रखना चाहते हैं तो सर सैयद अहमद खान के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखें। लेकिन आप जो संशोधन ला रहे हैं इससे आप वही पुराना रूप दे रहे हैं, साम्प्रदायिक रूप दे रहे हैं। इसलिये जो आपने संशोधन रखा है मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

4.00 P.M.

SHRI K. K. MADHAVAN (Kerala): Sir, I have to contradict the Minister. Give me just one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Madhavan, I am calling the Members party-wise. This is not an occasion for discussion. The discussion has already taken place. Many Members have spoken. On amendments only the party-wise position is to be explained. That is how I am allowing them. Yes, Mr. Yadav.

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, मैं इस संशोधन का जो श्री त्रिलोकी सिंह जी ने पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन के संबंध में जो बातें माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कही हैं उनसे ऐसा लगता है कि वे कुछ भ्रम में रहे हैं। अगर वे वास्तविक बातों और तथ्यों पर सही रूप में जाते तो जो विवरण उन्होंने इस विधेयक के संबंध में दिये हैं उनको देने की जरूरत नहीं पड़ती। शिक्षा मंत्री जी ने ऐतिहासिक तथ्यों की तरफ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तरफ और दूसरी बातों की तरफ इशारा किया है। वे सभी बातें, मैं समझता हूं, इस बिल के संबंध में आवश्यक नहीं थी। उन्होंने जो उदाहरण दिये उनको भी देने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे शिक्षा मंत्री जी भी मानते हैं और हमारी सरकार भी मानती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केवल मुसलमानों द्वारा प्रस्थापित की गई थी। इस यूनिवर्सिटी की जब स्थापना हुई तो इसका नाम मोहमडन एग्लो-ओरिएन्टल कालेज अलीगढ़ था और उसी ऐतिहासिक तथ्य को यहां पर उद्घाटित किया गया है और उसकी व्याख्या की गई है। शिक्षा मंत्री जी ने यह बात कही कि यह कालेज उस युनिवर्सिटी के साथ मर्ज नहीं किया गया था। मैं समझता हूं कि यहां पर इस कालेज के मर्ज होने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जब इस कालेज की स्थापना हुई तो उसका नामकरण इसी नाम से किया गया था और इसका नाम मोहमडन एग्लो-ओरिएन्टल कालेज, अलीगढ़ रखा गया था। बाद में चल कर यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी बनी और इसके साथ यह नाम इनकारपोरेट कर दिया गया। पार्लियामेन्ट के एक्ट से यह युनिवर्सिटी बनी। यह सही है कि पिछली बार इस विधेयक में कुछ संशोधन किये गये जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस लगी। मैं इस संबंध में यह भी कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ही यह संशोधन लाये हैं। दोनों कांग्रेस पार्टियां इस मामले में पूर्ण रूप से एक हैं, यह बात आप देख रहे हैं। हम सब इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी का एक माइनोरिटी केरेक्टर है और हमें उसको उसी रूप में मान्यता देनी चाहिए। मैं यह आशा करता हूं कि यह संशोधन इस सदन द्वारा स्वीकार होने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री इतनी उदारता अवश्य रखेंगे और इस सदन के प्रति सम्मान रखते हुए इस बिल को दूसरे सदन में भी पास कराने

की चेष्टा करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Triloki Singh, do you want to reply?

श्री त्रिलोकी सिंह : जी हां । मान्यवर, मुझे केवल इतना ही कहना है कि माननीय मंत्री जी ने पुन कानूनी सलाह को उठाया है और यह कहा है कि पार्लियामेंट को अधिकार प्राप्त है कि वह इस कानून में जब चाहे तरमीम करे या इसको रद्द कर दे । मैं समझता हूं कि इस पर तो कभी कोई विवाद नहीं रहा है और कभी किसी ने नहीं कहा कि पार्लियामेन्ट को कानून बनाने का हक नहीं है मैंने पहले ही निवेदन किया है कि अगर कोई विपरीत हालत होती तो मैं यह बिल सदन में नहीं लाता । मंत्री जी को तमाम अख्तियार हैं और वे दोनों हाउसों में अपने बहुमत के आधार पर अलीगढ़ युनिवर्सिटी एक्ट को चाहें तो बिल्कुल रिपील कर सकते हैं । इस मामले में उनसे हमारा कोई झगड़ा नही है । मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि महमडन एग्लो-ओरिएन्टल कालेज इसके लिए एक न्यूक्लीयस बना । जिस प्रकार से सेन्ट्रल हिन्दू कालेज बनारस युनिवर्सिटी के लिए न्यूक्लीयस बना । यह कालेज डा० एनी बेसेन्ट ने स्थापित किया था । यूनिवर्सिटी एक्ट के प्रिएम्बल में यह साफ लिखा हुआ है कि —

"Whereas it is expedient to establish and incorporate a teaching and residential Muslim University at Aligarh and to dissolve the Societies registered under the Societies' Registration Act, 1860 which are respectively known as the Muhammadan Anglo-Oriental College and the Muslim University Association...".

मोहमडन एग्लो-ओरियंटल कालेज को एक करोड़ रुपये की जायदाद, इमारत, सारा फर्नीचर, इक्वीपमेंन्ट सब का सब दिया गया—

to transfer and vest in the same University all properties and rights of the said Society under the Muslim University Foundation Committee.

मेरी समझ में नहीं आता है मान्यवर, कि यह कम्युनल भावना कहां से आती है । अगर हम अपने को मुसलमान कहे तो हम कम्युनल हो गये, अगर हम अपने को हिन्दू कहें तो कम्युनल हो गये, इसाई कहें तो कम्युनल हो गये । मैं मान्यवर मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में ऐसा प्रबंध कीजिये ताकि लोग न अपने को हिन्दू कहें, न अपने को मुसलमान कहें बल्कि वे अपने को हिन्दुस्तानी समझें । अगर वे अपने को हिन्दुस्तानी समझेंगे तो यह दिक्कत हल हो जायेगी । इसीलिये मैंने यह जुर्रत की कि यह तरमीमी बिल इस आदरणीय सदन में पेश किया और मैं आज भी सदन के हर तरफ के सदस्य से यही निवेदन करना चाहता हूं बड़ी नम्रतापूर्वक कि खुदा के लिये हिन्दी बनिये । जब आप हिन्दी बनेंगे तो आपका देश तरक्की करेगा । और इसी गरज से मैंने इसको पेश किया । मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पेश की गई तरमीम स्वीकार की जायेगी ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): The question is:

3. "That at page 1, for Clause 2, the following Clause be substituted, namely:

'2. In section 2 of the Aligarh Muslim University Act, 1920 (hereinafter referred to as the principal Act), for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) 'University' means the educational institution of their choice established by the Muslims of India which originated as the Mohammadan Anglo-Oriental College, Aligarh and which was subsequently incorporated as Aligarh Muslim University."'"

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): The question is:

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill."

The question was proposed.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Now we shall take up clause 3. There are no amendments.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1 (Short title and commencement)

SHRI TRILOKI SINGH: Sir, I beg to move:

2. "That at page 1, line 4, for the figure '1977' the figure '1979' be substituted."

Sir, this is a consequential amendment and I do not think there will be any opposition to it.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): The question is:

2. "That at page 1, line 4, for the figure '1977' the figure '1979' be substituted.".

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): The question is:

"That Clause 1, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): There is one amendment to the Enacting Formula by Shri Triloki Singh.

SHRI TRILOKI SINGH: Sir, I beg to move:

1. "That at page 1, line 1, for the word 'Twenty-eighth' the word *'Thirtieth'* be *substituted."*

Sir, this is a consequential amendment.

The question was proposed

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): The question is:

1. "That at page 1, line 1, for the word "Twenty-eighth' the word 'Thirtieth' be substituted."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI TRILOKI SINGH: Sir, I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was put and the motion was adopted.

श्री कल्प नाथ राय : सरकार हार गयी, इस्तीफा दे दो ।

DR. RAM KRIPAL SINHA: The House has reversed your previous amendment. It is against you.

श्री कल्प नाथ राय : जनता सरकार हार गई यह प्रधान मंत्री को बताने की रक्षा करे ।